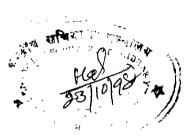
HRA AN USIUA The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUCHORITY



सं० 164] No. 164] मई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 30, 1998/श्रावण 8, 1920 NEW DELHI, THURSDAY, JULY 30, 1998/SRAVANA 8, 1920

वाणिज्य मंत्रालय

पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय

जांच-श्रूरुआत की अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 1998

विषय : मैक्सिको से एक्रीलिक फाइबर के आयात के बारे में पाटनरोधी जांच की शुरूआत

सं. 21/1/98-ए.डी.डी.— मैसर्स इण्डियन एक्नीलिक्स लिमिटेड, पशुपित एक्नीलोन लिमिटेड और कंसोलिडेटेड फाइबर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड ने सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष (जिसे इसके बाद प्राधिकारी कहा जाएगा) मैक्सिको से एक्नीलिक फाइबर के पाटन का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की है और पाटनरोधी जांच करने तथा पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

 शामिल उत्पाद तथा जांच का क्षेत्र: इस मामले में जांच के अधीन उत्पाद मैक्सिको मूल का या वहां से निर्यात किया गया एक्रीलिक फाइबर है।

एक्रीलिक फाइबर का वर्गीकरण सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के सीमाशुल्क उप-शीर्ष सं. 5501 के अन्तर्गत किया जाता है। किन्तु यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

- 2. स्थिति:- याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि भारत में निम्नांकित के द्वारा एक्रीलिक फाइबर का उत्पादन किया जा रहा है :-
 - (क) इण्डियन एक्रीलिक्स लिमि.
 - (ख) पशुपति एक्रीलोन लिमि.
 - (ग) कंसोलीडेटेड फाइबर एण्ड कैमिकल्स लिमि.
 - (घ) जे.के. सिन्थेटिक्स लिमि.
 - (ङ) इण्डियन पैटोकैमिकल कारपो.

इसके साथ-साथ, एक्रीलिक फाइनर्स के उत्पादकों के फोरम ने इस याचिका का समर्थन किया है। याचिकाकर्त्ता ने दावा किया है कि अभी जे.के. सिन्थेटिक्स लिमि. प्रचालन में नहीं है। याचिकाकर्त्ताओं का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का 74% है। इस प्रकार, याचिकाकर्त्ता घरेलू उद्योग की ओर से वर्तमान याचिका दायर करने की योग्यता रखते हैं। 2054 GI/98

- 3. इसमें शामिल देश: वर्तमान जांच में शामिल देश मैक्सिको है।
- 4. **समान वस्तुएं:** याचिकाकर्त्ता ने यह दावा किया है कि उसके द्वारा उत्पादित वस्तुएं मैक्सिकों से निर्यातित या वहां के उद्गम वाली वस्तुओं के समान वस्तु है। याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित वस्तुओं को नियमों के अर्थ के अन्तर्गत मैक्सिकों से निर्यातित वस्तुओं के समान वस्तु माना जा रहा है।
 - 5. पाटन और पाटन सीमाः
 - (क) सामान्य मूल्य : याचिकाकर्ता ने उन कीमतों के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है जिस कीमत पर मैक्सिको के घरेलू बाजार में उपभोग के लिए एक्रीलिक फाइबर ब्रेचा जाता है। मैक्सिको में संदर्भाधीन वस्तुओं के सामान्य मूल्य के बारे में पर्याप्त प्रथम दृष्ट्या प्रमाण हैं।
 - (ख) निर्यात कीमत: याधिकाकर्ता ने वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है जो कि 64.81 रु. प्रति किग्रा. की निर्यात कीमत दर्शाते हैं। मैक्सिको से संदर्भाधीन वस्तुओं की निर्यात कीमत के बारे में पर्याप्त प्रथम दृष्टया प्रमाण हैं।
 - (ग) ऊपर बताए गए अनुसार सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करने के बाद, पाटन की सीमा न्यूनतम सीमाओं से बहुत अधिक है।

ऐसे पर्याप्त प्रथम दृष्ट्या प्रमाण हैं कि मैक्सिको में विचाराधीन उत्पाद का सामान्य मूल्य उस कीमत से काफी ज्यादा है जिस कीमत पर इसका निर्यात भारत में किया गया, प्रथम दृष्ट्या इससे यह संकेत मिलता है कि निर्यातकों द्वारा मैक्सिको से संदर्भाधीन वस्तुओं का पाटन किया जा रहा है।

- 6. श्रित तथा कारणात्मक संबंध: घरेलू उद्योग से संबंधित विधिन्न आर्थिक संकेतकों जैसे उत्पादन, बिक्री, बाजार हिस्सा, लाभ-हानि इत्यादि से सामूहिक और समग्र रूप से प्रथम दृष्ट्या यह संकेत मिलता है कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। ऐसे पर्याप्त प्रथम दृष्ट्या प्रमाण हैं कि विचाराधीन उत्पाद के आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।
- 7. पाटनरोधी जांच की शुरुआत : इसलिए प्राधिकारी उक्त देश के उद्गम वाली या वहां से निर्यात की गई संदर्भाधीन वस्तुओं के कथित पाटन के अस्तित्व, मात्रा और प्रभाव के बारे में पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हैं।
 - 8. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अप्रैल, 1997 से 31 मार्च, 1998 (12 महीने) की है।
- 9. सूचना प्रस्तुत करना: मैक्सिको के निर्यातकों और भारत के प्रभावित आयातकों को अलग से पत्र भेजा जा रहा है जिससे कि वे निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित तरीके से सम्बद्ध सूचना भेज सकें और निर्दिष्ट प्राधिकारी, वाणिज्य मंत्रालय, महानिदेशालय, पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110001 को अपने विचारों से अवगत करा सकें। कोई अन्य इच्छुक पार्टी भी इस जांच से संबंधित अपने अनुरोध निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित तरीके से नीचे दी गई समय-सीमा के भीतर भेज सकते हैं।
- 10. समय-सीमा: वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रूप में भेजी जानी चाहिए जिससे वह ऊपर बताए गए पते पर प्राधिकारी के पास इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से चालीस दिनों के अन्दर पहुंच जाए। किन्तु, वे ज्ञात निर्यातक और आयातक, जिन्हें अलग से लिखा जा रहा है, उन्हें अलग से लिखे गए पत्र की तारीख से चालीस दिनों के अन्दर सूचना देनी है।
- 11. **सार्वजनिक फाइल की जांच :** नियम 6 (7) के अनुसार, कोई भी इच्छुक पक्ष अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के गैर-गोपनीय रूपान्तर वाली सार्वजनिक फाइल की जांच कर सकते हैं।
- 12. अगर कोई इच्छुक पक्ष सूचना देने से मना करता है या अन्य प्रकार से उचित समय के अन्दर आवश्यक सूचना नहीं देता है, या जांच में महत्वपूर्ण रूप से रुकावट डालता है, तब प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच-परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को ऐसे सुझाव दे सकते हैं जो वह उचित समझें।

MINISTRY OF COMMERCE

DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 1998

Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning import of Acrylic Fibres from Mexico

No. 21/1/98-ADD.—M/s. Indian Acrylics Ltd., Pasupati Acrylon Ltd. and Consolidated Fibres and Chemicals Ltd. have filed a petition in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) alleging dumping of Acrylic Fibres from Mexico and requested for anti-dumping investigations and levy of anti-dumping duties.

1. Product involved and scope of investigation: The product under investigation in the present case is Acrylic Fibre originating in or exported from Mexico.

Acrylic Fibre is classified under custom sub-heading Nos. 5501 and 5503 of the Customs Tariff Act. The Classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigations.

- 2. Standing: The petitioner has claimed that Acrylic Fibre is being produced in India by the following:
 - (a) Indian Acrylics Ltd.,
 - (b) Pasupati Acrylon Ltd.,
 - (c) Consolidated Fibre and Chemicals Ltd.,
 - (d) JK Synthetics Ltd.,
 - (e) Indian Petrochemical Corpn.

Further, the Forum of Acrylic Fibres Manufacturers has supported the petition. The petitioner has claimed that JK Synthetics Ltd. is presently not in operation. The petitioners account for 74% of the total Indian production. The petitioners, therefore, satisfy the standing to file the present petition, on behalf of the domestic industry.

- 3. Country(les) involved: The country involved in the present investigation is Mexico.
- 4. Like goods: The petitioner has claimed that goods produced by it are like articles to the goods exported or originating from Mexico. Goods produced by the petitioner are being treated as like articles to the goods exported from Mexico within the meaning of the Rules.

5. Dumping and dumping margin:

- (a) Normal value: The petitioner has claimed normal value based on the prices at which Acrylic Fibre is sold for consumption in the domestic market in Mexico. There is sufficient prima facie evidence with regard to normal value of the subject goods in Mexico.
- (b) Export price: The petitioners have claimed export price on the basis of data published by Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics, Calcutta, which indicate an export price of Rs. 64.81 per kg. There is sufficient prima facie evidence with regard to export price of the subject goods from Mexico.
- (c) Considering the normal value and export price as detailed above, the dumping margin is significantly higher than the de-minimus limits.

There is sufficient prima facie evidence that the normal value of the product under consideration in Mexico is significantly higher than the price at which it has been exported to India, indicating, prima facie, that the subject goods are being dumped by the exporters from Mexico.

- 6. Injury and casual link: The various economic indicators relating to domestic industry such as production, sales, market share, profit/loss etc. collectively and cumulatively, prima facie, indicate that the domestic industry has suffered injury. There is sufficient prime facie evidence that the imports of the product under consideration have caused injury to the domestic industry.
- 7. Initiation of Anti-Dumping investigation: The Authority, therefore, initiates anti-dumping investigations into the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the said country.

- 8. **Period of investigation:** The period of investigation for the purpose of the present investigations is 1st April, 1997 to 31st March, 1998 (12 months).
- 9. Submission of Information: The exporters in Mexico and the importers in India known to be concerned are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Designated Authority, Ministry of Commerce, Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties, Udyog Bhavan, New Delhi-110011. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.
- 10. Time limit: Any information relating to the present investigations should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are, however, required to submit the information within forty days from the date of letter addressed to them separately.
- 11. Inspection of Public File: In terms of rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.
- 12. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

RATHI VINAY JHA, Designated Authority